तिब्बत देश

सं. राष्ट्र : मानवाधिकरों का खेल और नपुंसक अम्पायर

हर साल 10 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर की सरकारें और सामाजिक संगठन मानवाधिकारों और लोकतंत्र के बारे में लंबी कसमें खाते हैं। यह सिलसिला 1948 में तबसे चलता आ रहा है जब संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। संयोग से इस घोषणा को इस साल छह दशक पूरे हुए हैं। क्योंकि सं. राष्ट्र को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों समेत 192 देशों की सरकारों का समर्थन और चंदा हासिल है इसलिए यह भी उम्मीद की जाती है कि आम लोगों के मानवाधिकारों को कुचलने वाली सरकारों, आतंकवादी संगठनों और इसी तरह की अन्य ताकतों के खिलाफ यह संस्था कारगर कार्रवाई करेगी। ऐसे में यह स्वभाविक ही है कि साठ साल से दुनिया भर में शांति, भाईचारे और मानवाधिकारों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले और दुनिया के सबसे बड़े तथा खर्चीले संगठन से वे लोग भी कुछ उम्मीदें रखें जिनके मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं।

लेकिन दुर्भाग्य से इस संगठन का इतिहास देखने पर जो तस्वीर बनती है उससे तो यही लगता है कि धीरे–धीरे यह संगठन एक ऐसी व्यवस्था के शिकंजे में आ चुका है जिसमें केवल ऐसे लोगों के मानवा–धिकारों के हितों के लिए शोर मचाया जा सकता है या कुछ कार्रवाई की जा सकती है जिनके हित सं. राष्ट्र के भीतर प्रभावशाली किसी बड़े राजनीतिक–आर्थिक गिरोह के हितों से सीधे जुड़े हुए हों। लेकिन इन मामलों में भी यह चौधरी संगठन केवल उसी हद तक तक जाकर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाता है जहां से किसी दूसरे बड़े विरोधी गिरोह के हितों पर गंभीर खतरा न पैदा होने लगे। कहना ज्यादती नहीं होगा कि सं. राष्ट्र का 63 साल का पूरा इतिहास इन गिरोहों की सुविधा के अनुसार मानवाधिकार संबंधी मामलों को निबटाने या उनकी अनदेखी करने की एक कवायद का इतिहास है।

ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनमें मानवाधिकारों के गंभीर और एकदम खुल्लमखुल्ला उल्लंघन के बावजूद इस संगठन ने पूरी बेशर्मी के साथ सिर्फ इसलिए अपनी आंखें फेर लीं कि इन पर कोई कदम उठाने से किसी एक ताकतवर लॉबी के हितों को आंच पहुंचेगी। सूडान में दारफुर और बर्मा जैसे मामलों में इस संगठन की असहाय नपुसकता के सबसे ताजा उदाहरण इन दिनों दुनिया के सामने हैं। तिब्बत का मामला इनमें सबसे पुराना और शायद सबसे शर्मनाक है। 1949 में जब चीन की पीएलए सेना ने तिब्बत के पूर्वी प्रांतों पर जबरन कब्जा जमाया उस समय सं.राष्ट्र ने इस कारण इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया कि तिब्बत इसका सदस्य नहीं था। बाद में जब चीन सरकार ने 1950–51 में पूरे तिब्बत को हड़पने के लिए कदम उठाने शुरू किए तब मानवाधिकारों और लोकतंत्र की ठेकेदारी करने वाले इस संगठन ने यह कहकर मुंह फेर लिया कि चीन तो सं.राष्ट्र का मेंबर नहीं है इसलिए उसके बारे में पारित किसी प्रस्ताव का असर नहीं होगा। और उसके बाद 1959 में जब चीनी सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों से दुखी तिब्बती जनता के जनउभार को कुचलने के लिए चीन ने वहां नरसंहार शुरू किया तब तक चीनी शासन वहां इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि सं. राष्ट्र का सारा उत्साह इस पर 'चिंता' जताने और इसकी 'निंदा' करने तक ही सीमित रह गया। सं. राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों के कमीशन ने तब तिब्बत में चीन की इस कार्रवाई को खुले शब्दों में एक 'जातीय नरसंहार' की संज्ञा दी थी। उसने यह भी माना कि तिब्बत पर चीनी हमले से पहले तिब्बत अलग देशा था और चीन का हिस्सा नहीं था।

कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी कब्जे के खिलाफ उठे इस जनउभार के पहले दौर में ही कम से कम 80 हजार तिब्बतियों की हत्या कर दी गई। इसी दौर में अपनी जान बचाने के लिए वहां के धार्मिक शासक दलाई लामा को भागकर पड़ोसी भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इस हत्याकांड से चिंतित सं.राष्ट्र की महासभा ने 1959 में तिब्बती जनता के मानवाधिकारों के हितों में एक प्रस्ताव पारित करके चीन सरकार से मांग की थी कि वह इस नरसंहार को रोके और वहां मानवाधिकारों को बहाल करे। लेकिन चीन ने इसे अनदेखा कर दिया और सं. राष्ट्र ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाद में 1961 और 1965 में इसी प्रस्ताव को दोहरा कर सं.राष्ट्र ने केवल इसी सच्चाई को रेखांकित किया कि मुंहजुबानी चिंता जताने के अलावा कोई ठोस कदम उठाने की न तो उसकी औकात है और न इच्छा।

बाद में जब भारत की पहल पर ताइवान को हटाकर उसकी जगह बीजिंग की कम्युनिस्ट 'पीपल्स रिपब्लिक आफ चायना' सरकार को 'असली चीन' के रूप में सदस्यता दी गयी तब उम्मीद की जा रही थी कि अब यह संगठन तिब्बत पर पारित तीन प्रस्तावों पर अमल के लिए चीन सरकार पर दबाव डालेगा। लेकिन हुआ ठीक उलटा। उसके बाद तो चीन की दादागीरी के आगे घुटने टेकते हुए सं.राष्ट्र की सभी कमेटियों और संगठनों से तिब्बत संबंधी सभी कार्यक्रमों को लपेट दिया गया। यहां तक कि उसे जुड़े दस्तावेज़ भी हटा दिए गए। अब तो चीन के साथ व्यापार के लालच और चीनी वीटो के आगे नतमस्तक सरकारों ने सं. राष्ट्र में तिब्बत पर चर्चा तक बंद कर दी है। और तो और, मानवाधिकारों की सं.रा. परिषद में कई साल से जब भी चीन के भीतर मानवाधिकारों का सवाल उठता है तब इस मुद्दे को कार्रवाई में शामिल करने की वोटिंग में ही रद्द कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि केवल यही वह मौका होता है जब भारत और पाकिस्तान सरकारें चीन के पक्ष में मतदान करके किसी मामले पर समान राय व्यक्त करती है।

इस साल मानवाधिकार दिवस के मौक पर दुनिया भर में तिब्बत समर्थक संगठनों ने सं.रा. मुख्यालय के अलावा ओलंपिक समिति मुख्यालय और चीनी दूतावासों पर प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में 'स्टूडेंट्स फार ए फ्री टिबेट' ने तिब्बत पर चीन का 'रिपोर्ट कार्ड' भी पेश किया जिसमें चीन सरकार को 'एफ–माइनस' ग्रेड मिला है। स्विट्ज़रलैंड में प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक कमेटी के अधिकारियों से मिलकर उन्हें याद दिलाया कि 2008 के ओलंपिक खेल बीजिंग को देते समय कमेटी ने कहा था कि इससे चीन सरकार को अपने यहां मानवाधिकार की हालत सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन तब से आज तक का रिकार्ड दिखाता है कि वहां मानवाधिकारों की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है। कमेटी अधिकारियों ने इसे सुना लेकिन उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया कि तिब्बत की टीम को भी बीजिंग ओलंपिक में एक अलग टीम के रूप में शामिल किया जाए।

उधर चीन सरकार ने इस बात की पुख्ता व्यवस्था कर ली है कि चीन के मानवाधिकारवादी, लोकतंत्र समर्थक संगठन या तिब्बत, सिंकियांग और मंगोलिया जैसे उपनिवेशों के लोग ओलंपिक के दौरान प्रदर्शन न कर पाएं। अगर ऐसा प्रदर्शन हो तो विदेशी टीवी लाइव प्रसारणों में इसकी फुटेज को रोकने की भी पक्की व्यवस्था कर ली गई है। यह शर्त रखी गई है कि किसी विदेशी प्रसारण को 6 मिनट के लूप में चलाने बाद ही प्रसारित होने दिया जाएगा ताकि समय रहते ऐसी फुटेज को रोका जा सके। ताजा खबर यह है कि मीडिया की आजादी और मानवाधिकारों का ढोल पीटने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीवी संगठनों ने इस चीनी आदेश को घुटने टेक कर स्वीकार कर लिया है। विज्ञापन का लालची मीडिया, डरपोक ओलंपिक कमेटी, स्वार्थी सरकारें और उन सबका प्रतिनिधित्व करने वाला एक नपुंसक संगठन –– मानवाधिकार की बात न छेड़ी जाए तो बेहतर होगा।

— विजय क्रान्ति

भिक्षुओं को समारोहों से रोकने के लिए द्रेपुंग मठ में चीनी सैनिक : उपनिवेश का प्रसाद

दलाई लामा को सम्मान पर तिब्बत में धूम

चीनी सेना ने समारोहों पर पाबंदी लगाई, पूर्वी तिब्बत में दीवाली, द्रेपुंग विहार पर चीनी सैनिकों का कब्जा

दलाई लामा को सम्मानित किये जाने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम ल्हासा में अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण रहे जबकि पूर्वी तिब्बत के कई हिस्सों में तो तिब्बतियों ने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया।

14 नवंबर तिब्बत से मिले नवीनतम चित्रों से इस बात की पुष्टि हुई है कि दलाई लामा को अमेरिका में सम्मानित किये जाने के दिन द्रेपुंग मठ के बाहर चीनी सैनिकों का भारी जमावड़ा था। दरअसल ये सैनिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वहां के भिक्षु दलाई लामा को सम्मानित किये जाने के उपलक्ष में कोई समारोह कर सकते हैं। इससे पहले उस सुबह भिक्षुओं ने इस पुरस्कार की खुशी में मठ की एक दीवार पर सफेदी करने का प्रयास किया था जिसे स्थानीय चीनी पुलिस ने रोक दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के लिए अभियान चलाने वाले संगठन इंटरनेशनल कैंपेन फार टिबेट को ये चित्र एक पर्यटक से इंटरनेट से प्राप्त हुए।

दलाई लामा को 17 अक्तूबर को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान कांग्रेशनल गोल्ड मैडल से सम्मानित किया गया था। कूटनीतिक क्षेत्रों में इसे उन्हें मिले नोबेल शांति पुरस्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिब्बत से बाहर आए इन फोटुओं से साफ होता है कि सशस्त्र सैनिकों ने द्रेपुंग विहार को सील कर दिया और घेर लिया। द्रेपुंग तिब्बत के तीन सबसे बड़े मठों में गिना जाता है। तिब्बत पर चीन के जबरन कब्जे से पहले इस मठ में पांच हजार से ज्यादा भिक्षु रहते थे लेकिन आजकल चीन सरकार ने इनकी संख्या को कुछ सौ तक सीमित रखा हुआ है। इससे पहले भी कई मौकों पर द्रेपुंग मठ के भिक्षु चीनी कब्जे के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों में भाग ले चुके हैं।

फोटुओं से पता चलता है कि सैनिक इस विहार के बाहर जमा हुए और निकटवर्ती पहाड़ी पर भी उनका भारी जमावड़ा रहा। एक पर्यवेक्षक ने बताया कि ''विहार के आस पास के पेड़ों और पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों तथा सिपाहियों का भारी जमावड़ा था।''

इसी सप्ताह ल्हासा की सड़कों पर पुलिस के जांच नाके भी देखे गये। पुलिस और सेना ने ये कदम लोगों को अमेरिकी समारोह के उपलक्ष्य में किसी तरह के धार्मिक आयोजन या समारोह जैसी कोई गतिविधि आयोजित करने से रोकने के लिये उठाये थे। हांगकांग के समाचार पत्र मिंग पाओ की रपट के अनुसार वाशिंगटन समारोह की सुबह चीनी सशस्त्र पुलिस ने द्रेपुंग में भिक्षुओं को दीवारों पर सफेदी पोतने से रोक दिया। जब एक भिक्षु ने सफेदी के घोल को चलाने के लिए कनस्तर में ब्रश घुमाने का प्रयास किया तो उसके सिर पर लाठी से वार किया गया। एक तिब्बती द्वारा चीनी भाषा की एक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उसके बाद इस भिक्षु पर पुलिस वालों ने लातों और घूंसों की बरसात कर दी।

इस सूत्र ने बताया कि इस हमले के बाद भिक्षु वहां से चले गए और सशस्त्र पुलिस विहार में प्रवेश कर गई। इन सैनिकों को विहार के पार्किंग क्षेत्र में अभ्यास करते भी देखा गया।

श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को इस दौरान विहार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह भिक्षुओं को बाहर नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि भिक्षुओं को भोजनालय में भी नहीं जाने दिया गया।

एक रपट के अनुसार सीलबंदी के बाद 26 अक्तूबर को पहली बार कुछ श्रद्धालुओं को विहार के भीतर जाने की अनुमति दी गई। एक ब्लागसाइट पर डाली गई एक रिपोर्ट में ल्हासा में मौजूद लोगों के हवाले से कहा गया है कि सात नवंबर को ही भिक्षुओं को बाहर जाने की अनुमति दी गई वह भी सीमित समय के लिये। द्रेपुंग में स्थिति अब भी तनावपूर्ण है क्योंकि भिक्षुओं पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

दलाई लामा को अमेरिका में सम्मानित किये जाने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम ल्हासा में अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण रहे जबकि पूर्वी तिब्बत के कई हिस्सों में तो तिब्बतियों ने पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। पूर्वी तिब्बत में लाबरांग में खुशी मना रहे और प्रार्थना कर रहे कुछ तिब्बतियों को अस्थाई तौर पर हिरासत में लिये जाने के समाचार हैं। लेकिन निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों ने इस अवसर पर दुनिया भर में समारोह किए।

यूरोपीय सांसदों ने चीन सरकार को दलाई लामा से बात करने की सलाह दी

तिब्बत में मानवाधिकारों की हालत पर चिंता जताई

ब्रसेल्स, 12 नवंबर ब्रसेल्स में तिब्बत पर यूरोपीय संसदीय सम्मेलन ने आज चीन द्वारा तिब्बती नागरिकों के मानवाधिकारों के निरंतर दमन पर चिंता जताई। सम्मेलन ने यूरोपीय संघ तथा यूरोप की राष्ट्रीय सरकारों का आह्वान किया कि वे चीन–तिब्बत विवाद के राजनीतिक समाधान के लिये दबाव बनायें।

इस सम्मेलन में 20 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, मानवाधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता और ओलंपिक स्वर्ण पद विजेता शामिल थे। इसका सम्मेलन की मेजबानी यूरोपीय संघ के टिबेट इंटरग्रुप ने की और यह ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद भवन में हुआ।

सम्मेलन का उद्घाटन टिबेट इंटरग्रुप के अध्यक्ष थामस मान तथा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हेंस ग्रेत पोइतरिंग ने किया। इसमें तिब्बत की पर्यावरणीय स्थिति तथा बीजिंग–2008 ओलंपिक खेलों पर दो कार्यशालाएं भी हुईं। श्री पोइतरिंग ने चीन की सरकार तथा परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच संपर्क बहाल होने का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने चीन की सरकार से आग्रह किया कि वह इस लंबी समस्या के राजनीतिक समाधान का लक्ष्य रखते हुए गंभीर बातचीत पर ध्यान दे।

श्री मान ने कहा, ''यूरोपीय संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सदस्य देश इस तरह की नीतियां अंगीकार करेंगे जो तिब्बती लोगों के भयावह दमन को समाप्त करने वाली पहल को बढ़ावा दें।'' सम्मेलन ने तिब्बत पर पारित दो प्रस्तावों में से एक में तिब्बत के पर्यावरण की स्थिति और निरंतरता के लिये विभिन्न खतरों को रेखांकित किया गया है। ये खतरे चीन सरकार की नीतियों के कारण ही पैदा हुए हैं जिनमें संसाधनों का अनाप शनाप दोहन तथा पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप, तीव्र शहरीकरण तथा तिब्बती क्षेत्र में गैर तिब्बती लोगों को बड़ी संख्या में बसाना शामिल है।

श्री थामस मान ने कहा, ''टिबेट इंटरग्रुप चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ द्वारा पार्टी सम्मेलन में अक्तूबर 2007 में जताई गई प्रतिबद्धता की सराहना करता है जिसमें उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही थी। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि तिब्बती लोगों के लिये उचित स्वायत्तता का कार्यान्वयन नहीं कर पाना खुद चीन सरकार की विफलता है।''

सम्मेलन की दूसरी कार्यशाला में प्रतिभागियों ने चीन में अगले साल होने जा रहे ओलंपिक खेलों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने सामाजिक तथा राजनीतिक बदलावों में गत ओलंपिक खेलों की भूमिका पर विचार विमर्श किया और कहा कि ओलंपिक 2008 भी चीन एवं तिब्बत में सकारात्मक बदलावों का प्रतिनिधि बन सकता है।

निवार्सित तिब्बती सरकार की वरिष्ठ सांसद सुश्री डोलमा ग्यारी ने यूरोपीय संसद का आह्वान किया कि वह परम पावन दलाई लामा तथा चीन सरकार के बीच बातचीत को अपने समर्थन को मजबूत करे।

चीन–तिब्बत बातचीत के बारे में दलाई लामा के दूत श्री केलसांग ग्यालत्सेन ने कहा, ''चीनी नेतृत्व की प्राथमिकता अपने लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान तथा आदर प्राप्त करना है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्वीकार्यता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।'

तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान के यूरोपीय संघ नीति निदेशक विनसेंट मेट्टन ने कहा कि नीति निर्माताओं को अपनी सरकारों का आह्वान करना चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि चीन की कथनी और करनी संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक संधि के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान करे। सम्मेलन ने इसके साथ ही चीन का आह्वान किया कि वह प्रेस की आजादी तथा अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू पत्रकारों द्वारा स्वतंत्र रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करे जिसमें तिब्बत की यात्रा और रिपोर्टिंग की आजादी भी शामिल हो।

मन्न ने कहा, ''हम राष्ट्रपति हू जिंताओ के नाम अपील जारी करेंगे कि ओलंपिक एवं उसके बाद भी अभिव्यक्ति, धार्मिक मान्यता तथा सहयोग की स्वतंत्रता का आदर किया जाये।''

सम्मेलन में जर्मन धावक डीटर बाउमन्न और चौथे शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले पीटर स्टेस्टन शामिल हुए। पीटर यूरोपीय संसद के सदस्य भी हैं। तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान की यूरोप निदेशक सुश्री सेरिंग जांपा ने कहा, ''इस सम्मेलन ने तिब्बत के समर्थकों को मिलने तथा तिब्बती मुद्दों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर विचार करने का बढ़िया मंच उपलब्ध कराया।'' उन्होंने कहा कि तिब्बत मामले पर यूरोप के सभी नीति निर्धारकों की भागीदारी की हम सराहना करते हैं।

सम्मेलन का आयोजन यूरोपीय संसद के इंटरग्रुप फार टिबेट, ब्यूरो द टिबेट, ब्रसेल्स तथा इंटरनेशनल यूरोप में कैंपेन फार टिबेट के सहयोग से किया गया।

तिब्बत पर पारित दो प्रस्तावों में से एक में तिब्बत के पर्यावरण की स्थिति और निरंतरता के लिये विभिन्न खतरों को रेखांकित किया गया है। ये खतरे चीन सरकार की नीतियों के कारण ही पैदा हुए हैं जिनमें संसाधनों का अनाप शनाप दोहन तथा पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप, तीव्र शहरीकरण तथा तिब्बती क्षेत्र में गैर तिब्बती लोगों को बड़ी संख्या में बसाना शामिल है।

तिब्बत के लिए प्रदर्शन मे भारतीय समर्थक भारी संख्या में थे : साझा दर्द, साझा संघर्ष

तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन

नई दिल्ली में भारतीय तिब्बत समर्थकों का विशाल और अविस्मरणीय प्रदर्शन

तिब्बत पर उपनिवेशवादी नियंत्रण बनाए रखना एभ्य समाज की नैतिकता को भारी चुनौती है। धरती के इस आखिरी उपनिवेश के बारे में भारत सरकार को ठीक वैसी ही नीति अपनानी चाहिए जैसी वह द. अफ्रीका और दूसरे उपनिवेशों के बारे में अपनाती रही है।

इस साल का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों के लिए विशेष महत्व का रहा क्योंकि इसके साथ ही इन संगठनों द्वारा मनाया जा रहा 'तिब्बती संघर्ष के समर्थन में सघन वर्ष' सम्पन्न हुआ। दस दिसंबर के दिन भारत के कई शहरों और कस्बों में इन संगठनों ने तिब्बती आजादी के समर्थन में प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं का आयोजन किया।

इस अवसर पर भारत के तिब्बत समर्थन संगठनों के केंद्रीय संयोजक संगठन कोर ग्रुप फॉर तिबेतन कॉज़ ने भारत सरकार से अपील की कि वह तिब्बत के बारे में अपनी नीति पर नए सिरे से विचार करके इसे एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान वाली नीति का रूप दे क्योंकि इसके कारण खुद भारतीय हितों को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

केंद्रीय स्तर पर जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया कि एक सभ्य दुनिया में चीन द्वारा तिब्बत पर 1951 से लगातार और खुल्लमखुल्ला उपनिवेशवादी नियंत्रण बनाए रखना एभ्य समाज की नैतिकता को भारी चुनौती है। इसमें भारत सरकार से मांग की गई कि एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता प्रेमी देश होने के नाते भारत को धरती के इस आखिरी उपनिवेश के बारे में ठीक वैसी ही नीति अपनानी चाहिए जैसी वह द. अफ्रीका और दूसरे उपनिवेशों के बारे में अपनाती रही है। बयान में भारत सरकार से कहा गया है कि वह हर मामले में चीन सरकार के आगे रिरियाने और उसे खुश करने वाली नीति को त्यागते हुए आत्मसम्मान का परिचय दे। भारत सरकार को यह भी याद दिलाया गया कि अगर वह भारत की उत्तरी सीमा पर शांति चाहती है और चीन की ओर से भारत तथा दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को सुरक्षित रखना चाहती है तो इसका एकमात्र हल यही है कि भारत और चीन के बीच एक स्वतंत्र बफर देश के रूप में तिब्बत के ऐतिहासिक चरित्र को बहाल किया जाए।

इस अभियान का मुख्य प्रदर्शन नई दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ जिसके बारे में प्रेक्षकों की राय है कि पिछले कई साल में तिब्बत के समर्थन में भारतीय नागरिकों का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसका आयोजन भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों ने किया। पिछले वर्षों के दौरान इस दिन किए जाने वाले अधिकांश प्रदर्शन तिब्बती संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं। इसे सफल बनाने में जिन संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें भारत का तिब्बत समर्थक संसदीय मंच, भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय कमेटी फार एक्शन आन टिबेट, फ्रेंड्स ऑफ टिबेट, हिमालय परिवार, यूथ लिबरेशन फ्रंट फार टिबेट, स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट, महिला पंचायत, सोशलिस्ट फ्रंट, समाजवादी विचार मंच, समाजवादी शिक्षक मंच और विद्यार्थी युवजन सभा आदि प्रमुख थे। इनका साथ देने के लिए तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला संघ समेत कई तिब्बती संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी रैली में भाग लिया।

इस रैली में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, ब्रजभूषण तिवारी और श्री विभूति नारायण सिंह, सुश्री सुमन कृष्णकांत, श्री इंद्रेश कुमार, श्री सुरेंद्र किशोर, डा. आनंद कुमार, डा. कुलदीप अग्निहोत्री, लामा चोसफेल ज़ोत्पा, पत्रकार कुलदीप नैयर, डा. हीरापाल नेगी, सुश्री रेणु गंभीर, डा. रघुवीर सिंह कपूर, डा. अनिल ठाकुर, डा. एस. सिद्दीकी, श्री अशोक जैन, श्री प्रेम सिंह, श्री अवधेश कुमार,श्री राकेश कुमार जैसे चर्चित तिब्बत समर्थक भी शामिल थे।

अधिकांश वक्ताओं ने भारत सरकार की तिब्बत नीति की आलोचना करते हुए भारत सरकार को सलाह दी कि वह अपनी दब्बूपने वाली नीति को छोड़कर आत्मसम्मान और साहस भरी नीतियां अपनाये। कई वक्ताओं ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि

जहां एक ओर दुनिया भर में सरकारें, संसदें और सामाजिक संगठन दलाई लामा जी को अपने यहां बुलाकर सम्मान दे रहे हैं और उनके शांति संदेश के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत सरकार खास आदेश जारी करके अपने अधिकारियों और नेताओं को दलाई के नागरिक अभिनंदन में भाग लेने से भी रोक रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत सरकार निकट भविष्य में दलाई लामा जी को भारतीय संसद के साझा अधिवेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करेगी और आज के युग के इस सबसे बड़े शांतिदूत को 'भारत–रत्न' जैसे सम्मान से शोभित करेगी।

रैली में अपने भाषण में डा. आनंद कुमार ने कहा कि पिछले 10 साल से चीन लगातार कभी सिक्किम और कभी अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर अपना हक जताता आ रहा है। उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी कि वह तिब्बत के सवाल पर उसे खुलकर समर्थन देने की नीति अपनाए। वरिष्ठ पत्रकार श्री कुलदीप नैयर ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि भारत सरकार चीन सरकार को खुश करने के लिए अब अपने मंत्रियों को भी दलाई लामा के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से रोकने लगी है। लेकिन उन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन की तारीफ करते हुए तिब्बतवासियों को आश्वासन दिया कि भारत की जनता का समर्थन उन्हें मिलता रहेगा।

सुश्री सुमन कृष्णकांत ने तिब्बती आंदोलन के अनुशासन और अहिंसा में विश्वास की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एक दिन उनकी लगन जरूर रंग लाएगी। भारत–तिब्बत सहयोग मंच के संयोजक डा. कुलदीप अग्निहोत्री ने कहा कि तिब्बत पर चीनी कब्जे से पहले मानसरोवर पूरी तरह मुक्त था और भारतीय तीर्थयात्री बिना रोकटोक वहां दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन अब इस पवित्र स्थान पर चीन का कब्जा है और वह भारत के कई इलाकों पर भी गिद्ध नज़र जमाए हुए है। उन्होंने भारतीय जनता को चेताया कि भारत को तोड़ने के चीनी इरादों पर उसे कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता से अपील की कि भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उसे चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। सुश्री रेणु गंभीर ने कहा कि तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद चीन की साम्यवादी सरकार भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है।

अहमदाबाद में जोरदार प्रदर्शन

विश्व मानवाधिकार दिवस पर प्रदर्शनों की इस

मैसूर की रैली में भारी संख्या में तिब्बतियों ने भाग लिया : आजादी के लिए

अखिल भारतीय श्रंखला के अंतर्गत अहमदाबाद में बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ जिसका आयोजन कोर ग्रुप और स्थानीय तिब्बती स्वेटर सेलर समूह ने मिलकर किया। कोर ग्रुप के पश्चिमी क्षेत्र के संयोजक एडवोकेट श्री संदीप ज्योतिकर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भारी संख्या में भारतीय समर्थकों ने भाग लिया। नेहरू ब्रिज रुपाली थिएटर के सामने हुई सभा को अध्यक्ष श्री पी जी ज्योतिकर, श्री गणेशराव तावड़े, श्री त्रिभुवन तथागत, श्री कल्पेश वोरा तथा श्री संदीप ज्योतिकर ने संबोधित किया।

मेरठ में समारोह

अंतर्राष्ट्रीय भारत–तिब्बत सहयोग समिति, मेरठ की ओर से मैसानिक लॉज में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विशिष्ट अतिथि डा. के सी गुप्ता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तिब्बत के जाने माने समर्थक और गांधीवादी कार्यकर्ता श्री कुल भूषण बक्शी ने की। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण उन विद्यार्थियों का सम्मान था जिन्होंने पिछले तीन माह के दौरान 34 स्कूलों और कालेजों में तिब्बत निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते थे। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए विद्यार्थियों के अलावा संबंधित स्कूलों और कालेजों के प्राचार्यों और अध्यापकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

श्री कुल भूषण बक्शी ने अपने भाषण में कहा कि मानव अधिकारों का जैसा हनन पिछले 58 साल में तिब्बत में हुआ है वैसी दुखद मिसाल दुनिया के इतिहास में और कहीं नहीं है। श्री वाजपेयी ने दलाई लामा जी द्वारा तिब्बत वासियों को स्वायत्ता दिलाने संबंधी प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां

जहां एक ओर दुनिया भर में सरकारें, संसदें और सामाजिक संगठन दलाई लामा जी को अपने यहां बुलाकर सम्मान दे रहे हैं और उनके शांति संदेश के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारत सरकार खास आदेश जारी करके अपने अधिकारियों और नेताओं को दलाई के नागरिक अभिनंदन में भाग लेने से भी रोक रही है।

नई दिल्ली में जंतर मंतर पर तिब्बत समर्थक : उपनिवेशवाद से टक्कर

चीन सरकार मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन कर रही है और तिब्बतियों को उनके ही देश में अल्पसंख्यक बनाने में लगी हुई है। डा. के सी गुप्ता ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि तिब्बत में इतने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्तव्य का वहन नहीं किया है।

भोपाल में प्रदर्शन

भोपाल में इस अवसर पर महात्मा गांधी तिब्बत मुक्ति आंदोलन के संयोजक डा. महेश यादव ने एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी कब्जे का विरोध करने के लिए प्रतीक के रूप में एक जेल के बाड़े में बंद होकर प्रदर्शन किया। दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल संगठनों से अपील की गई कि वे बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करके चीन सरकार की तिब्बत पर उपनिवेशवादी नीति का विरोध जताएं।

डा. यादव पिछले 11 साल से भारत, यूरोप और दूसरे कई देशों के बीसियों शहरों में तिब्बत की आजादी के समर्थन में प्रदर्शन कर चुके हैं। इन दिनों वह 50 शहरों में तिब्बत की आजादी और दलाई लामा जी के शांतिपूर्ण अभियान के समर्थन में 'जय भारत–जय तिब्बत' यात्रा का आयोजन कर रहे हैं।

नागपुर में 24 घंटे का अनशन

भारत तिब्बत मैत्री संघ और तिब्बती युवा कांग्रेस की नागपुर शाखाओं ने वहां इस मौके पर राजाभाऊ खोबरागड़े मूर्ति के निकट 24 घंटे के उपवास का आयोजन किया। इस उपवास का आयोजन तिब्बत में चीनी कब्जे में फंसे हुए तिब्बत में मानवाधिकारों की चिंताजनक हालत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया। अनशनकारियों ने दुनिया के नागरिकों से यह अपील की कि 12 साल से चीन की हिरासत में रहने वाले 11वें पंचेन लामा की रिहाई के लिए चीन सरकार पर दबाव बनाया जाए।

नागपुर और रांची की सभाओं में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि चीन ने 1995 से पंचेन लामा के 11वें अवतार गेदुन छ्योकि नीमा जी और उनके माता पिता को हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन चीन सरकार न तो पंचेन लामा की सुरक्षा के बारे में दुनिया को कोई जानकारी दे रही है और न उन्हें रिहा कर रही है।

चंडीगढ़ में प्रार्थना और प्रदर्शन

चंडीगढ़ की रिजनल तिब्बती युवा कांग्रेस, तिबेतन फ्रीडम मूवमेंट और वहां के तिब्बत समर्थक भारतीय समर्थकों ने तिब्बती जनता के मानवाधिकारों और तिब्बत की आजादी के समर्थन में सैक्टर–16 के कला भवन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में दलाई लामा के चित्र और तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे। तिब्बती युवाओं को समर्थन देने के लिए ग्लोबल मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन श्री अरविंद ठाकुर भी आए। तिब्बती युवा कांग्रेस की चंडीगढ़ शाखा के अध्यक्ष श्री तेनज़िन थिनले ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत में मानवाधिकारों की खराब हालत का विवरण देते हुए भारत सरकार और दुनिया भर के देशों से अपील की कि वे इस नाजुक मौके पर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाते हुए चीन सरकार पर दबाव बनाएं। श्री अरविंद ठाकुर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि चीन सरकार तिब्बत के यूरेनियम भंडारों से अपनी परमाणु ताकत को बढाने में लगी हुई है और तिब्बत पर चीनी कब्जे के कारण भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रही है।

रांची में कार्यक्रम

झारखंड के भारत–तिब्बत सहयोग मंच और रांची के पोताला स्वैटर मार्किट के तिब्बती दुकानदारों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर महात्मा गांधी भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने दलाई लामा जी के शांतिपूर्ण तिब्बत मुक्ति आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया और दुनिया की जनता और सरकारों से अपील की कि वे दलाई लामा जी के प्रयासों को सक्रिय समर्थन दें। सभा में एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नामग्याल दोरजी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि चीन ने 1995 से पंचेन लामा के 11वें अवतार गेदुन छ्योकि नीमा जी और उनके माता पिता को हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन चीन सरकार न तो पंचेन लामा की सुरक्षा के बारे में दुनिया को कोई जानकारी दे रही है और न उन्हें रिहा कर रही है।

ग्वालियर में प्रार्थना

ग्वालियर में रहने वाले तिब्बतियों ने 10 दिसंबर को दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिलने की 18वीं सालगिरह के रूप में मनाया। इस मौके पर दलाई लामा जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई

और भोजन भंडारे का आयोजन किया गया। स्थानीय तिब्बती नेता श्री तेनज़िन शाडोन ने कहा कि दलाई लामा ने तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाया है।

मैसूर में रैली

मैसूर के भारत–तिब्बत मैत्री संघ और स्थानीय तिब्बती संगठनों ने संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहां तिब्बती महिला संगठन और स्थानीय वरिष्ठ तिब्बती नागरिकों ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय जाकर उन्हें तिब्बत के बारे में एक मांगपत्र सौंपा।

नगर के कई हिस्सों से होकर निकली रैली को सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टेन एच राजगोपाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। रैली में भाग लेने वाले लोगों में विधायक श्री थोंडा दरया, तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष श्री आर वासुदेवामूर्ति, भारत–तिब्बत मैत्री संघ के सचिव श्री वीरराज उर्स, उद्योगपति श्री एम गणपति, उद्योगपति श्री श्रीधर राज उर्स और श्री रामन्नावार, श्री कृष्ण गौडा, प्रो. प्रभाकर, श्री गुरू प्रसाद, मैत्री संघ के अध्यक्ष ग्रुप कैप्टेन एच राजगोपाल आदि मुख्य थे।

संयुक्त राश्ट्र मुख्यालय पर प्रदर्शन

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दूसरे कई देशों से भी इस तरह के प्रदर्शनों के समाचार प्राप्त हुए हैं। न्यूयार्क, लंदन, पैरिस और टोरांटो में रहने वाले तिब्बतियों और उनके स्थानीय समर्थकों ने प्रभावशाली प्रदर्शनों का आयोजन किया। अमेरिका में सक्रिय कई तिब्बत समर्थक संगठनों के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने न्यूयार्क में सं. राष्ट्र मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहां के प्रदर्शन के बाद वे 42वीं स्ट्रीट पर चलते हुए वे वहां के चीनी वाणिज्य दूतावास गए जहां उन्होंने तिब्बत के भीतर चीन सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का ब्यौरा देने वाली एक रिपोर्ट जारी की। रास्ते में वे 'तिब्बत तिब्बतियों के लिए' और 'वन वर्ल्ड – वन ड्रीम : फ्री टिबेट' (एक विश्व, एक सपना : आजाद तिब्बत) जैसे नारे लगा रहे थे। दूसरा नारा बीजिंग ओलंपिक के नारे 'वन वर्ल्ड – वन ड्रीम' की पैरोडी है जो इन दिनों दुनिया भर में चलने वाले तिब्बत समर्थक प्रदर्शनों का मुख्य नारा बन चुका है।

इससे पहले सुबह तिब्बती युवा कांग्रेस ने सं. राष्ट्र कार्यालय में एक ज्ञापन दिया जिसके साथ उपरोक्त रिपोर्ट भी लगाई गई थी। इस ज्ञापन में विश्व संगठन को याद दिलाया गया कि कुचले गए और जबरन कब्जाए गए देशों की जनता के प्रति सं. राष्ट्र की गंभीर जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे निभाना है।

भोपाल में तिब्बती मैसूर की रैली में भारी संख्या में तिब्बतियों ने भाग लिया : आजादी

दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में तिब्बत की आजादी के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले संगठन स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट के उपनिदेशक तेनज़िन दोरजी ने अपने भाषण में कहा कि यह संतोष की बात है कि दुनिया में इस तरह के दिन पर मानवाधिकारों को याद किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी तिब्बत की जनता को उसके कई महत्वपूर्ण मानवाधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

चीनी वाणिज्य दूतावास पर किए गए प्रदर्शन के दौरान जब चीनी अधिकारियों ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया तक पांच प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति का वर्णन देने वाला 4 फुट लंबा एक रिपोर्ट कार्ड दूतावास की लॉबी के दरवाजे पर चिपका दिया। इस रिपोर्ट कार्ड में तिब्बत के भीतर बात कहने की आजादी, धार्मिक आजादी, सभा करने की आजादी और विचारों की आजादी जैसे विषयों पर चीन सरकार को सबसे खराब अंक 'एफ–माइनस' दिए गए हैं।

इन प्रदर्शनों से चिढ़े हुए चीनी दूतावास ने अपने उप वाणिज्य दूत कांग चेन के नाम से एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि ''तिब्बत का सवाल धार्मिक या सांस्कृतिक सवाल नहीं बल्कि चीन की सार्वभौमिकता और भूगौलिक एकता का विषय है।''

इस मौके पर भारत में कई अन्य स्थानों से भी प्रदर्शनों के समाचार आए हैं। इनमें धर्मशाला, दार्जिलिंग, शिमला, मनाली, बंगलूर, चेन्नई, भंडारा, चंडीगढ़ और बालकुप्पे आदि के प्रदर्शन भी शामिल हैं।

–प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर **विजय क्रान्ति**

प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति पर 4 फुट लंबा एक रिपोर्ट कार्ड दूतावास की लॉबी के दरवाजे पर चिपका दिया। इसमें तिब्बत के भीतर बात कहने की आजादी, धार्मिक आजादी और सभा करने की आजादी जैसे विषयों पर चीन सरकार को सबसे खराब अंक 'एफ–माइनस' दिए गए हैं।

कैमरे की

1. रोम में नोबेल विजेताओं के सम्मेलन में भाग लेने से पहले दलाई लामा
2. 20 नवंबर को दिल्ली में 'तिब्बत समस्या समाधान में भारत की भूमिका' प
3. अपनी जापान यात्रा में दलाई लामा ने 18 नवंबर को ईसे जिंगयू मंदिर क
4. नई दिल्ली के दरियागंज में जैन संप्रदाय के अहिंसा पर्यावरण साधना मं
5. 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली की विशाल रैली में
6. भारतीय जनसंचार संस्थान के दिल्ली केंद्र के विद्यार्थियों ने धर्मशाला की
7. मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भारत भर में तिब्बत समर्थक प्रदर्शन अ
8. 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर मैसूर में भी एक बड़ा प्र
9. धर्मशाला के मिस–तिब्बत समारोह में इस बार तेनज़िन दोलमा को तिब्बत
10. दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विवि में 'सत्याग्रह शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम

♦ आंखों देखी

ा आंख से

ने वहां के मेयर वालटर वेलत्रोनी के साथ मुलाकात की।
र सम्मेलन में प्रो. सामदेांग रिंपोछे और श्री प्रेम कुमार धूमल ने भाग लिया।
की यात्रा की। मंदिर के वरिष्ठ जापानी धार्मिक नेताओं ने उनकी आगवानी की।
दिर के उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ जैन गुरुओं के साथ दलाई लामा ने भाग लिया।
भारत के तिब्बत समर्थकों ने भारी संख्या में भाग लिया।
यात्रा करके तिब्बती समाज और उसकी स्थिति का निजी अनुभव लिया।
ौर सभाएं की गईं। भोपाल के प्रदर्शन में डा. महेश यादव और उनके सहयोगी।
दर्शन हुआ जिसमें तिब्बत समर्थक भारतीय कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे।
सुंदरी का ताज़ पहनाया गया। साथ हैं पिछली मिस–तिब्बत सेरिंग चुगडाक।
म्मेलन : गांधीवादी मार्ग का वैश्वीकरण' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया।

(फ़ोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

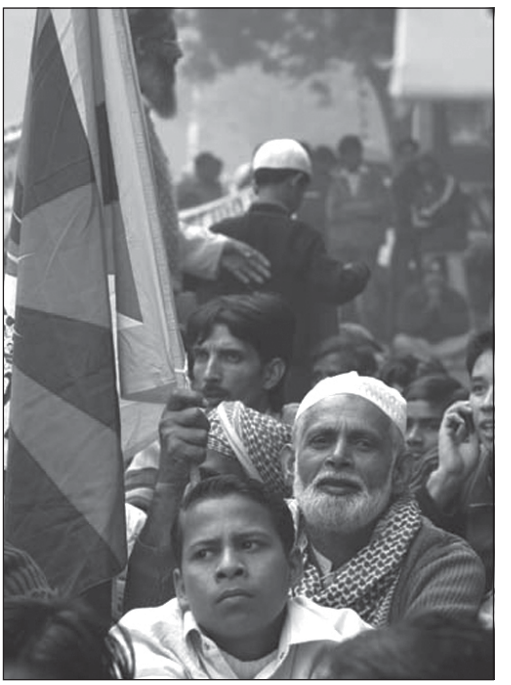

दक्षिण भारत के एक राजमार्ग पर तिब्बती पदयात्री : भाई के साथ संवाद

तिब्बती आज़ादी के लिए पदयात्रा

बेंगलूर से चेन्नई के बीच 365 किमी की पदयात्रा में तिब्बती युवाओं का भारतीय जनता से जनसंपर्क

तिब्बत की आजादी के बारे में भारतीय जनता में जाग्रति पैदा करने के उद्देश्य से तिब्बती युवा कांग्रेस के लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने बंगलोर से चेन्नई तक 22 दिन की शांति पदयात्रा की। यह यात्रा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन शुरू होकर चित्तूर, पालमनेर, रानीपेट, वेल्लूर और कांचीपुरम के रास्ते 365 किमी की दूरी तय करके 31 दिसंबर को चेन्नई पहुंची। पदयात्रियों में कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अलावा कई भिक्षु और भिक्षुणियां भी शामिल थीं।

हम ऐसे कानून को तुरंत वापस लेने की मांग करते है जो एक धर्म विरोधी सरकार को तिब्बती बुद्ध धर्म में दखल करने और उसे परम पावन दलाई लामा समेत किसी भी वरिष्ठ अवतारी लामा की नियुक्ति और पुष्टि की अनुमति देता है।

पदयात्रियों में भारत के नौ ऐसे क्षेत्रों से आए तिब्बती कार्यकर्ता थे जहां तिब्बती रहते हैं। ये क्षेत्र हैं धर्मशाला, कर्नाटक में बालकुप्पे, हुंसूर और मुंडगोड, दार्जिलिंग, दिल्ली, भंडारा, मैनपाट और बंगलोर। पदयात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले शहरों, कस्बों और गांवों में इन पदयात्रियों ने जनसभाएं करके और लोगों के साथ सीधी बात करके उन्हें तिब्बती जनता पर चीन सरकार के जुल्मों, तिब्बत पर चीनी कब्जे से पैदा हुए हालात और इस कारण भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर उसके बुरे असर के बारे में बताया।

इस पदयात्रा के माध्यम से तिब्बत के जिन पहलुओं पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता का ध्यान खींचने का प्रयास किया। इस बारे में युवा कांग्रेस का बयान यहां प्रस्तुत है :

तिब्बत के लिये आज़ादी : हम तिब्बत के 2000 साल के राष्ट्रीय इतिहास को देखते हुए चीन से तिब्बत की पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। तिब्बत तिब्बतियों का है इसलिए तिब्बत में केवल तिब्बती रह सकते हैं। चीन के साथ हमारा रिश्ता केवल पड़ोसी का है। हम तिब्बत में गैर कानूनी कम्युनिस्ट चीनी शासन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतिहास, नस्ल, संस्कृति तथा भाषा के मामलों में तिब्बत और चीन एकदम अलग–अलग देश हैं।

चीनी 'आदेश–5' को वापस लिया जाये : चीन ने तिब्बत के अवतारी लामाओं के अवतार बारे में, जिन्हें चीन में 'जीवित बुद्ध' और तिब्बत में 'तुलकू' कहा जाता है, एक नया कानून बनाया है जिसे 'आर्डर नं. 5' कहा जा रहा है। यह एक सितंबर 2007 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के अनुसार अब से तिब्बत में पुनर्जन्म लेने वाले किसी भी अवतारी लामा को तब तक 'वास्तविक' तुलकू या 'जीवित बुद्ध' नहीं माना जाएगा जबतक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में चलने वाले सरकारी विभाग उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर नहीं लगा देते। इसका मतलब यह है कि इसके बाद चीन सराकर दलाई लामा सहित किसी भी वरिष्ठ अवतारी धर्मगुरू के पद पर अपनी मर्जी के व्यक्ति को बिठा सकेगी। यह तिब्बत के धार्मिक मामलों में सरासर दखलंदाजी है और तिब्बत में धार्मिक आजादी के दमन के इस चीनी कदम की हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। हम ऐसे कानून को तुरंत वापस लेने की मांग करते है जो एक धर्म विरोधी सरकार को तिब्बती बुद्ध धर्म में दखल करने और उसे परम पावन दलाई लामा समेत किसी भी वरिष्ठ अवतारी लामा की नियुक्ति और पुष्टि की अनुमति देता है।

तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को तुरंत रोका जाए : हम तिब्बत में तिब्बती पहचान को नष्ट करने के लिए चलाए जा रहे मौजूदा चीनी जनसंख्या अतिक्रमण को तुरंत रोकने की मांग करते हैं। चीन इस काम के लिए तिब्बत में लाई गई नई रेल लाइन का भी जमकर दुरुपयोग कर रहा है। हमारी मांग है कि तिब्बत में तिब्बतियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनका दमन तुरंत रोका जाए। तिब्बत–चीन रेलवे लाइन का इस्तेमाल तिब्बत में चीनी लोगों को चीन से लाकर तिब्बत में बसाने के लिये किया जा रहा है ताकि तिब्बती जनसंख्या को और अधिक हाशिये पर धकेला जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट करने तथा धीरे धीरे तिब्बती पहचान और संस्कृति को नष्ट करने के लिये किया जा रहा है।

तिब्बत को आजादी के बिना चीन में ओलंपिक

नहीं : तिब्बत और चीन में चीन के खराब मानवाधिकार रिकार्ड को देखते हुए हम 2008 के ओलंपिक खेलों के लिये बीजिंग को मेजबान राष्ट्र का दर्जा वापस लेने की मांग करते हैं। चीन ने अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी शासन के जरिये तिब्बत और चीन के 130 करोड़ लोगों का दमन किया है। हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मांग करते हैं कि वह चीन सरकार को तिब्बत और चीन में मानवाधिकार की स्थिति तुरंत सुधारने तथा ओलंपिक आंदोलन के आदर्शों पर खरा उतरने के लिये बाध्य करे।

सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाये: हम चीन सरकार से तिब्बत में सभी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त तत्काल रिहा करने की मांग करते हैं। इस बारे में तीन मामलों का संदर्भ नीचे दिया जा रहा है–

अ. गेदुन छ्योकि नीमा, तिब्बत के 11वें पंचेन लामा जिनका चीन सरकार तिब्बत ने 1995 में तब अपहरण कर लिया था जब वह छह साल के थे। इसके बाद उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दसवें पंचेन लामा की 1989 में संदेहास्पद मृत्यु को देखते हुए हमें 11वें पंचेन लामा की कुशलता एवं सुरक्षा के बारे में गंभीर संदेह है।

ब. तुलकू तेनज़िन देलेक को चीन सरकार ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने' के आरोप में बिना स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया के आजीवन कैद की सजा सुनाई है।

स. रोंग्ए आद्राक को 19 नवंबर 2007 को आठ साल की सजा सुनाई गई। उनका अपराध यह था कि उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया और परम पावन दलाई लामा को तिब्बत लौटने, पंचेन लामा की रिहाई तथा तिब्बत की आजादी का आह्वान किया

बीजिंग ओलंपिक का विरोध: बीजिंग ओलंपिक 2008 का समय पास आता जा रहा है और चीन इस आयोजन का इस्तेमाल तिब्बत पर अपने कब्जे को वैध ठहराने के मंच के रूप में इस्तेमाल करेगा। खेल आयोजनों की प्रक्रिया में ओलंपिक मशाल को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ले जाना शामिल है जो चीन में नहीं बल्कि तिब्बत में है। हमारा विरोध अभियान तिब्बत के स्वतंत्र होने तक जारी रहेगा। इस अभियान के माध्यम से तिब्बत के भीतर उत्पीड़न झेल रहे हमारे भाई बंधुओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण आजादी के अपने वादे को टीवाईसी निभायेगी। वह तिब्बत का समर्थन करने के लिये भारत की जनता का भी आभार व्यक्त करती है।

मावाधिकार दिवस पर मैसूर के प्रदर्शन में तिब्बती शरणार्थी : अनवरत संघर्ष

तिब्बत पर चीनी कब्जा सं.राष्ट्र की विफलता का जीवित दस्तावेज़

विश्व मानवाधिकार दिवस पर तिब्बती युवा कांग्रेस

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर वैश्विक घोषणा पत्र को अंगीकार किया जिसमें कहा गया है कि ''सभी मानव समान एवं समकक्ष अधिकारों और बुनियादी आजादी के साथ पैदा हुए हैं।'' पर दुर्भाग्य से इस घोषणा के बाद आधी शताब्दी से ज्यादा समय बाद भी दुनिया का यह सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज मानवाधिकारों की वैश्विकता और अक्षुणता तथा इसमें संजोए गए मूल अधिकारों की नैतिकता को वास्तविकता की भाषा में अनुवादित नहीं कर पाया है।

तिब्बत पर 1949 में चीन के क्रूर हमले के बाद से ही तिब्बत संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर विफलता का एक जीवित दस्तावेज बना हुआ है। इस कब्जे के चलते जहां 12 लाख से अधिक तिब्बतियों को जान से हाथ धोना पड़ा है और तिब्बत के भीतर मूल मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन हो रहा है।

एक अगस्त 2007 को पूर्वी तिब्बत में एक बंजारे रोंग्ए आद्राक को गिरफ्तार कर लिया गया। आद्राक का दोष इतना था कि उसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 80वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में 'दलाई लामा तिब्बत लौटें', ' पंचेन लामा को रिहा करो' तथा 'आजादी चाहता है तिब्बत' आदि नारे लगाये। उसे ये नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

हाल ही में उसके मामले की सुनवाई हुई है और वह फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। उसका अपराध महज इतना है कि उसने तिब्बती लोगों की सही

1949 में चीन के क्रूर हमले के बाद से ही तिब्बत संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर विफलता का एक जीवित दस्तावेज बना हुआ है। इस कब्जे के चलते जहां 12 लाख से अधिक तिब्बतियों को जान से हाथ धोना पड़ा है और तिब्बत के भीतर मूल मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन हो रहा है।

अपेक्षाओं को उजागर किया। इस घटना के बाद से ही चीनी अधिकारियों ने पूर्वी तिब्बत में व्यापक 'देशभक्ति – अभियान' चलाया है जिसके तहत अनेक तिब्बतियों तथा आद्राक के शुभचिंतकों को गिरफ्तार किया गया है। चीनी अधिकारी इनका उत्पीड़न कर रहे हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म के 'जीवित बुद्ध' माने जाने वाले अवतारी धर्मगुरुओं के चयन के बारे में चीन के धार्मिक मामलों के प्रशसान ने 14 धाराओं वाले कदमों की घोषणा की है जिन्हें एक सितंबर 2007 से लागू कर दिया गया। यह पहल कम्युनिस्ट चीन की ओर से सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध संस्कृति को दरकिनार करने या मिटाने के प्रयासों की नई कड़ी है। इसके अलावा ये प्रयास बताते हैं कि चीन परम पावन दलाई लामा सहित अन्य तिब्बती धार्मिक नेताओं के प्रभाव को कमजोर करने के लिये कितना बेचैन है।

2008 के ओलंपिक खेलों को देखते हुए चीन ने तिब्बत के भीतर दमन बढ़ा दिया है। पूर्वी तिब्बती प्रांत आम्दो बोरा में पिछले दिनों कुछ तिब्बती युवाओं को इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने गांव में सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर आजादी समर्थक नारे लिखे।

आज भी चीन 11वें पंचेन लामा गेदुन छ्योकि नीमा के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है जिनका 1995 में अपहरण कर लिया गया था। तुलकू तेनज़िन देलेक को गलत तरीके से फंसाकर आजीवन कैद की सजा दी गई। अनेक तिब्बती अब भी सींखचों के पीछे हैं जो अपने मूल मानवाधिकारों से वंचित हैं जिन्हें सही सुनवाई का मौका तक नहीं दिया जा रहा।

चीन तो तिब्बती नस्ल तथा राष्ट्रीय पहचान को ही मिटाने पर तुला है। इसके लिये वह तिब्बत में हान चीनी नागरिकों को धड़ाधड़ बसा रहा है। नई रेल लाइन का इस्तेमाल इसी उद्देश्य में किया जा रहा है। इस तरह से, तिब्बत का सवाल केवल गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि यह एक अलग नस्ल, संस्कृति तथा राश्ट्रीय पहचान के रूप में तिब्बतियों के अस्तित्व का सवाल बन चुका है।

आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर तिब्बत युवा कांग्रेस तिब्बती जनता की ओर से चीन की कम्युनिस्ट सरकार से मांग करती है कि वह तिब्बती लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तुरंत रोके, सभी राजनीति बंदियों को रिहा करे तथा 60 लाख तिब्बतियों की चीन से आजादी की इच्छा और ऐतिहासिक तथ्यों का आदर करे।

–केंद्रीय कार्यकारिणी, तिब्बती युवा कांग्रेस

चीन तो तिब्बती नस्ल तथा राष्ट्रीय पहचान को ही मिटाने पर तुला है। इसके लिये वह तिब्बत में हान चीनी नागरिकों को धड़ाधड़ बसा रहा है। नई रेल लाइन का इस्तेमाल इसी उद्देश्य में किया जा रहा है। इस तरह से, तिब्बत का सवाल केवल गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि यह एक अलग नस्ल, संस्कृति तथा राश्ट्रीय पहचान के रूप में तिब्बतियों के अस्तित्व का सवाल बन चुका है।

दलाई लामा की कूटनीति तिब्बत को नहीं बदलेगी–चीन

बीजिंग, 1 नवंबर परम पावन दलाई लामा की इन्हीं दिनों कई पश्चिमी देशों की लगातार यात्राओं से चीन गंभीर चिंतित है। लेकिन चीन की सरकारी प्रतिक्रिया यही है कि इससे चीन शासित तिब्बत की स्थिति पर कोई असर नहीं होगा लेकिन इन देशों के साथ बीजिंग के संबंध खराब होंगे।

तिब्बत के पूर्व शासक और धार्मिक गुरू दलाई लामा का गत माह कनाडा तथा अमेरिका में वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आधिकारिक स्तर पर स्वागत किया था। इससे पहले चीनी विरोध के बावजूद आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ने उनसे मुलाकात की थी।

अपने नये राजनयिक कदम के तहत दलाई लामा ने दिसंबर में वेटिकन में पोप बेनेडिक्ट से मुलाकात की थी। चीन और वेटिकन में 1949 के बाद से कोई औपचारिक संबंध तो नहीं हैं लेकिन इस मुलाकात से आगे की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। दलाई लामा ने पोप बेनेडिक्ट से पहले पोप जान पाल से भी मुलाकात की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियू चियाछाओ ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा,''कुछ देश और लोग चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने की दुर्भावना के साथ दलाई लामा का साथ दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उनके प्रयासों से कुछ नहीं बदलेगा। यह चीन की संप्रभुता तथा भौगोलिक एकता में लगे चीनी लोगों को नहीं बदल सकती है और न तिब्बती देशभाइयों को।''

चीन सरकार दलाई लामा को 'राजनीतिक भगौड़ा' तथा 'देशद्रोही' जैसी गालियां देती रहती है। लियू ने वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैंपेन फार तिब्बत की उस रपट को भी खारिज कर दिया कि चीनी सैनिकों ने गत माह सीमा पार नेपाल जाने की कोशिश कर रहे तिब्बती लोगों पर गोली चलाई।

यहां उल्लेखनीय है कि कई महीने पहले नांग्पा ला के पास तिब्बत से भाग रहे तिब्बतियों पर चीनी सैनिकों की गोलीबारी में एक तिब्बती भिक्षुणी मारी गई थी। इस घटना को पास में ही डेरा डाले कुछ विदेशी पर्वतारोहियों के एक दल ने भी देखा था और उसे फिल्म पर उतारा था। तिब्बत की आजादी की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं ने बीजिंग को ओलंपिक–2008 की मेजबानी देने का भी विरोध किया है।

तिब्बत में चीनी दमन नस्लीय हिंसा को बढ़ा सकता है

हयूमन राइट वाच ने रोग्ये आद्राक की रिहाई की मांग की : बीबीसीन्यूज

न्यूयार्क, 9 नवंबर मानवाधिकार संगठन हयूमन राइट वाच ने आज कहा कि चीनी अधिकारियों को उस तिब्बती नागरिक रोंग्ये आद्राक को तुरंत रिहा करना चाहिए जिसने सार्वजनिक रूप से धार्मिक आजादी और दलाई लामा की तिब्बत यात्रा का आह्वान किया था।

सिचुआन प्रांत के दारसेदो स्थित पीपल्स कोर्ट ने रोंग्ये को 'अलगाववाद भड़काने' का दोषी पाया है। इस अपराध में रोंग्ये को तीन साल से लेकर आजीवन कैद की सजा हो सकती है।

बीबीसे के अनुसार संगठन के एशिया डाइरेक्टर ब्रेड एडम्स ने कहा, ''एक बार फिर चीन सरकार दलाई लामा की वापसी का आह्वान करने का साहस दिखाने वाले इस तिब्बती के खिलाफ मुकदमा चला रही है।'' उन्होंने कहा कि यह एक उदीयमान शक्तिशाली देश के मन में आत्मविश्वास के अभाव को दिखाता है। इस तरह का नस्लीय दमन ओलंपिक के आयोजन में नस्लीय तनाव को बढ़ा सकता है।

गौरतलब है कि रोंग्ये को राजनीतिक प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया था। लिथांग के इस तिब्बती की गिरफ्तारी एक अगस्त 2007 को हुई जब उन्होंने एक सरकारी समारोह में राजनीतिक प्रदर्शन किया था। लिथांग काउंटी सरकार ने चीनी जनमुक्ति सेना पीएलए के 80वें स्थापना दिवस पर इस समारोह का आयोजन किया था।

इस अवसर पर विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे जो यह कार्यक्रम तथा हर साल होने वाली चर्चित घुड़दौड़ देखने के लिए आये थे। समारोह शुरू होने से ठीक पहले रोंग्ये आद्राक ने मंच पर जाकर लिथांग विहार के मुख्य लामा लिथांग क्याबगोन को पारंपरिक तिब्बती स्कार्फ भी पेश किया था। रोंग्ये एक गांव योउरू का 52 साल का किसान है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी तथा आम लोग मौजूद थे। रोंग्ये ने वहां लगाए माइक पर जाकर सब के सामने 'दलाई लामा को तिब्बत लौटना चाहिए', 'पंचेन लामा को रिहा करो' और 'तिब्बत को आजादी' जैसे नारे लगाए। उन्होंने स्थानीय लोगों का आह्वान किया कि वे जल और जमीन के छोटे–छोटे मुद्दों को लेकर आपस में झगड़ना बंद करें। इसके बाद रोंग्ये मंच से उतरकर सीधे भिक्षु नाग्लू तेंजिन के पास गये और विहार के धार्मिक मामलों को लेकर उनके द्वारा अपनाये जा रहे दोहरे रवैये को उजागर किया। ये भिक्षु चीन सरकार द्वारा तिब्बतियों को चीनी शासन के प्रति आदर दिखाने के 'देशभक्ति शिक्षा अभियान' में सक्रियता से शामिल हैं। रोंग्ये ने नारेबाजी जारी रखी जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हो गए। कारज़े की स्थानीय पुलिस ने रोंग्ये को गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले गई।

रोंग्ये की सुरक्षा को लेकर चिंतित गांव के लोग लिथांग प्रांत कार्यालय गये और उन्हें तत्काल रिहा करने तथा स्थिति के बारे में जानकारी देने की मांग की। इन लोगों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया।

सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों को डराया धमकाया और हवा में गोलियां भी चलाई लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। मामले को गंभीर रूप लेता देख स्थानीय अधिकारियों ने अगले दिन रोंग्ये को रिहा करने का वादा किया। तब कहीं जाकर लोग अपने घर लौटने को तैयार हुए।

इस बारे में तीन अगस्त को जारी सरकारी बयान में कहा गया था कि रोंग्ये पर 'अलगाववाद को भड़काने' के आरोप लगाये गये हैं। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने रोंग्ये के अपराध को 'बेहद गंभीर' बताया। उसने कहा कि दलाई लामा की वापसी का आह्वान करके आद्राक ने 'चीन के विभाजन के प्रयास का अपराध' किया है।

इस तरह के अलगाववाद के प्रयासों को चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है। अदालत ने उसे उन स्थानीय विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का जिम्मेदार भी माना जो उसकी गिरफतारी के बाद हुए। तिब्बत पर 1951 में चीन के कब्जे के बाद से ही तिब्बती लोगों को मूल अधिकारों से सुनिश्चित तरीके से वंचित रखा जा रहा है। इन अधिकारों में अभिव्यक्ति, धार्मिक विश्वासों को मानने तथा सभा की आजादी शामिल है।

चीन स्वयं 1980 के दशक से दलाई लामा की तिब्बत यात्रा की बात करता रहा है लेकिन दोनों पक्षों में जारी बातचीत अब तक सिरे नहीं चढ़ सकी है। रोंग्ये के भाषण के बाद चीनी अधिकारियों ने क्षेत्र में एक अभियान चलाया और स्थानीय भिक्षुओं और कुछ प्रमुख लोगों से दलाई लामा की सार्वजनिक निंदा करने को कहा गया। इस बीच स्थानीय प्रशासन के कुछ वरिष्ठ तिब्बती अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह चीनी अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

हयूमन राइट्स वाच के एशिया डाइरेक्टर ब्रेड एडम्स ने कहा, ''एक बार फिर चीन सरकार दलाई लामा की वापसी का आह्वान करने का साहस दिखाने वाले इस तिब्बती के खिलाफ मुकदमा चला रही है।'' उन्होंने कहा कि यह एक उदीयमान शक्तिशाली देश के मन में आत्मविश्वास के अभाव को दिखाता है। इस तरह का नस्लीय दमन ओलंपिक के आयोजन में नस्लीय तनाव को बढ़ा सकता है।

जवाहर लाल नेहरू विवि के सम्मेलन में दलाई लामा : आज का गांधी

विवादों के निपटारे का एकमात्र रास्ता है बातचीत : दलाई लामा

सत्याग्रह की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

नई दिल्ली, 13 नवबंर तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता परम पावन दलाई लामा ने कहा है कि आज की दुनिया की समस्याओं का वास्तविक समाधान सिर्फ आपसी बातचीत और समझौते से ही संभव है।

वह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आठ दिन चलने वाले 'सत्याग्रह शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : गांधीवादी मार्ग का वैश्वीकरण' आयोजन का उद्घाटन कर रहे थे। इसका आयोजन विवि के समाज विज्ञान विभाग की ओर से तिब्बत के जाने माने समर्थन डा. आनंद कुमार ने किया। सम्मेलन का पहला भाग दिल्ली में और दूसरा भाग चंपारण में हुआ। इस अवसर पर दलाई लामा को सुनने के लिये बड़ी संख्या में विद्यार्थी, समाज शास्त्री तथा विदेशी प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के केवी ग्राउंड में मौजूद थे।

आज की वास्तविकता यही है कि एकतरफा जीत या एकतरफा हार असंभव है। इस माहौल में अगर कोई संघर्ष होता भी है तो आपको उसे बातचीत और समझौते से ही सुलझाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है।

दलाई लामा ने कहा : आज की वास्तविकता यही है कि एकतरफा जीत या एकतरफा हार असंभव है। उन्होंने कहा, ''इस माहौल में अगर कोई संघर्ष होता भी है तो आपको उसे बातचीत और समझौते से ही सुलझाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। हमें इस बात का स्पष्ट बोध होना चाहिए कि जब भी हमारे समक्ष कोई समस्या आये तो उसका समाधान केवल और केवल बातचीत ही है।''

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और ऐसे में बल का इस्तेमाल अव्यावहारिक है। बल का सीधा साधा मतलब युद्ध होगा जिसका किसी भी देश को लाभ नहीं होगा।

दलाई लामा ने अहिंसा की महत्ता पर भी जोर दिया और भारतीय युवाओं से इसे अपने जीवन के हर पहलू में अंगीकार करने को कहा।

उन्होंने कहा : न केवल अहिंसा की धारणा जरूरी है, बल्कि अहिंसा को व्यवहार में लाना भी बहुत जरूरी है। कोई भी बेहतर धारणा सिर्फ धरणा बने रहने पर अधिक प्रभावी नहीं होती, उसका कार्यान्यन करें।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने अपनी 'टूटी फूटी' अंग्रेजी में कहा, ''मैं गांधी का प्रशसंक हूं और मैं जहां भी जाता हूं उनका अहिंसा तथा करूणा का संदेश ले जाता हूं। उनकी शिक्षाएं धर्म तथा आस्थाओं की दीवारों से परे हैं।'' दलाई लामा ने कहा कि महात्मा गांधी का महत्व उनके 'अहिंसा' के सिद्धांत के क्रियान्वयन में है जो गांधी के ही सतत प्रयासों के कारण भारतीय राजनीति और सामाजिक सुधारों में अग्रणी बनी। हालांकि अहिंसा का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में सदियों सदियों से है।

लामा ने बड़ी विनम्रता से कहा : मैं कोई विद्वान नहीं हूं और मुझे विद्वानों वाला ज्ञान भी नहीं है। मैं तो बस अहिंसा को उसी रूप में अंगीकार करने की कोशिश करता हूं जैसा कि मैं सचाई, इमानदारी एवं करूणा के रूप में इसे मानता हूं।

उन्होंने कहा कि 'अहिंसा' की जीवनशैली अपनाने के लिये हमें अन्य मानव मात्र तथा उसके हितों के प्रति उचित आदर भाव लाना होगा। उन्होंने प्रतिहिंसा को गैर व्यवहारिक बताया और कहा कि किसी संघर्ष का सही समाधान सिर्फ रचनात्मक बातचीत में ही है।

उन्होंने कहा, ''यह देखना सुखद है कि युवा विद्यार्थियों में गांधी के सिद्धांतों में रुचि है। हमारे आज के युग के महान नेताओं ने भी उन्हें आदर्श माना है।'' दलाई लामा ने कहा कि भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना चाहिए और उसे मानना चाहिए।

कई बार ऐसा होता है कि तिब्बत समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों की रिपोर्टें न उपलब्ध होने के कारण 'तिब्बत देश' में प्रकाशित होने से रह जाती हैं। आयोजकों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रमों की रिपोर्ट और कुछ फोटो की फाइलें (लगभग 500 kb) हमें इस ई–मेल पते पर अवश्य भेजें :

tibbatdesh@yahoo.com

यदि ई–मेल न संभव हो तो इस पते पर भेजें :
'तिब्बत देश', भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र,
10-H लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024

दिल्ली में विश्व शांति स्तूप का लोकार्पण किया दलाई लामा ने

नई दिल्ली, 14 नवंबर दुनिया भर में शांति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये एक नये उल्लेखनीय स्थल, विश्व शांति स्तूप का दलाई लामा ने लोकार्पण किया।

तीस मीटर उंचाई के इस स्तूप को मध्यप्रदेश के सांची स्तूप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह सफेद है और दक्षिण दिल्ली में निजामुद्दीन के निकट रिंग रोड पर बने इंद्रप्रस्थ पार्क में है। इस अवसर पर दलाई लामा जी ने आशा व्यक्त की कि यह स्तूप मानव मूल्यों, शांति तथा भाईचारे को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि ढांचे का रूप नहीं बल्कि इसमें छिपा संदेश अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सलाह थी कि इन संदेशों का हिंदी अंग्रेज़ी अनुवाद भी उपलब्ध होना चाहिए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने इस स्मारक को दिल्ली का एक नया लैंडमार्क बताते हुए कहा कि यह शांति तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस स्तूप का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती के दिन ही हो रहा है।

इस स्तूप की पहल शांति स्तूप सोसायटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से की है। यह दुनिया में अपनी तरह का 74वां स्तूप है। जापान के एक प्रमुख बौद्ध निशिदास्तु फुजी ने अपने जवाहर लाल नेहरू अवार्ड की सारी राशि इस परियोजना को दान कर दी थी। स्तूप लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से तीन साल में बना।

स्मारक के चारों ओर जापानी तरीके से बना एक सुंदर राक गार्डन होगा। उद्घाटन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल ए आर किदवई, उड़ीसा के राज्यपाल एम सी भंडारे, दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना तथा प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी थे।

अधिक लंबे हैं भारत में जन्मे तिब्बत

नई दिल्ली, 12 नवंबर भारत में जन्मे और पले बढ़े तिब्बती अपेक्षाकृत अधिक लंबे हैं तथा उनमें कुछ और शारीरिक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं जो कि मूल तिब्बती लोगों में नहीं नजर आते। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, आईएसआई कलकत्ता के मानव शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला है।

इनका अध्ययन कहता है कि भारत में कम उंचाई में जन्मे तथा पले बढ़े तिब्बतियों की लंबाई मूल तिब्बत में जन्मे लोगों की तुलना में चार से पांच सेंटीमीटर अधिक है। आईएसआई की जैविक मानव विज्ञान इकाई के प्रमख रंजन गुप्ता ने इस बारे में कहा, ''सभी मानवीय जनसंख्या में अधिक उंचाई के पर्यावरण को तिब्बतियों ने सबसे बेहतर तरीके से अंगीकार किया है।'' उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब इस स्थिति में बदलाव आ रहा हो।

डा. गुप्ता तथा उनके सहयोगी विकल त्रिपाठी ने भारत में तीन अलग अलग उंचाई पर तिब्बती लोगों के शारीरिक ढांचे का अध्ययन किया है। इसमें लेह के निकट चोगलामसर भी है जो कि समुद्र तल से 3500 मीटर की उंचाई पर लद्दाख में है और जहां की जलवायु तिब्बत के समान ही है। इसके अलावा चंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में तिब्बती बस्ती है तथा बालकुप्पे जो कर्नाटक में है। बाद के दोनों स्थलों की समुद्र तल से उंचाई मात्र 100 मीटर की है।

इन शोधकर्ताओं का कहना है कि चोगलामसर में अधिक उंचाई पर कम आक्सीजन तथा कम पोषण के कारण हो सकता है कि तिब्बती लोगों की लंबाई प्रभावित होती हो। इन लोगों ने अपने निष्कर्षों को अमेरिकन जनरल आफ ह्यूमन बायोलाजी में पेश किया है। इनका कहना है कि समुद्र तल से कम उंचाई पर रहने वाले लोगों के पास सब्जियों तथा फलों के अधिक विकल्प मौजूद रहते हैं।

तिब्बती दंपति की तिब्बत से भारत तक की शांति यात्रा

बोध गया, 17 नवंबर शांति तथा सद्भाव का संदेश देने के लिये निकले एक तिब्बती दंपति ने तिब्बत से भारत तक की अपनी पदयात्रा को लगभग डेढ़ साल में पूरा कर लिया है। करदुन ने अपनी पत्नी सांगये डोलमा के साथ इस पदयात्रा के दौरान तिब्बत से नेपाल और भारत में बोधगया तक की यात्रा की जो 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी रही। इस दंपति ने अपनी इस यात्रा को यहां बोधगया में पूरा किया।

दंपत्ति की इस पद यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति का संदेश फैलाना और तिब्बत के पूर्व शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा की दीर्घायु की प्रार्थना करना था। बोधगया में इन दोनों ने महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में रखा है। इस मंदिर का निर्माण उसी बोधिवृक्ष के निकट किया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को उसके नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। दंपत्ति ने अपनी यात्रा की शुरुआत फरवरी 2006 में की थी।

अध्ययन कहता है कि भारत में कम उंचाई में जन्मे तथा पले बढ़े तिब्बतियों की लंबाई मूल तिब्बत में जन्मे लोगों की तुलना में चार से पांच सेंटीमीटर ज्यादा है। लद्दाख के चोगलामसर में अधिक उंचाई पर कम आक्सीजन तथा कम पोषण के कारण हो सकता है कि तिब्बती लोगों की लंबाई प्रभावित होती हो। इनका कहना है कि समुद्र तल से कम उंचाई पर रहने वाले लोगों के पास सब्जियों तथा फलों के अधिक विकल्प मौजूद रहते हैं।

चीन–अमेरिका के संबंधों में खटास

अमेरिका और चीन संबंधों के विषेशज्ञों का मानना है कि चीन द्वारा थैंक्सगिविंग के मौके पर अमेरिकी विमानवाहक को हांगकांग के बंदरगाह में खड़ा नहीं होने देना, पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यु बुश और दलाई लामा की मुलाकात का ही नतीजा है।

बीजिंग की पीपल्स यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रोफेसर शि यिन्होंग का कहना है, ''अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचना पुराना मसला है और चीन हमेशा से इस पर अपना असंतोष जताता आया है। लेकिन युद्धपोत को स्थान न देना यह दर्शाता है कि चीन बुश से नाराज है। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा परमपावन दलाई लामा को संसद के कांग्रेस गोल्ड मेडल से सम्मानित करना है।'' वाशिंगटन में एक समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार दलाई लामा के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए। इसी सप्ताह चीन सरकार उस समय दलाई लामा से और खफा हो गई जब उन्होंने चीन की अनुमति के बिना ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की दिशा में कदम बढ़ाया.

चीन में यूएसएस किटी हॉक को वापस लौटा दिया गया था जोकि पहले हांगकांग में ही खड़ा था। यह अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों का सामान्य विश्रामस्थल है। लेकिन कुछ ही घंटों में चीन ने अपने इरादे बदल दिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिउ जिआनचाओ ने रिपोर्टरों को बताया, ''यह फैसला मानवीय बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।''

तब से अब तक एक विमानवाहक, चार युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में 250 मील की दूरी पर हैं। इस फैसले के कारण अब इनका बेस जापान में होगा। यूएस पेसिफिक कमांड के टिमॉथी जे. कीटिंग के मुताबिक, ''कुछ दिन पहले दो माइनस्वीपरों को हांगकांग में ईंधन नहीं भरने दिया गया था और उन्हें खराब मौसम में इंतजार करना पड़ा था।''

अमेरिका और चीन के कई बिंदुओं पर तनाव जारी हैं जिनमें व्यापार, सैन्य मसले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से निपटने के उपाय आदि शामिल हैं। लेकिन चीन दलाई लामा के मामले में विशेष रुचि दिखा रहा है क्योंकि चीन उन्हें 'विभाजनकारी' मानता है। उसका मानना है कि वह चीन की संप्रभुता के लिए खतरा हैं। चीन के अधिकारियों का कहना है कि दलाई लामा गुपचुप तरीके से तिब्बत की आजादी के लिए संघर्ष चला रहे हैं। स्वायत्तता की बात तो मात्र एक छलावा है।

तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर दलाई लामा ने आगाह किया

हाम्बुर्ग, तिब्बत के पूर्व शासक और सर्वोच्च धर्मगुरू परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत में चीनी सैन्य बलों की कार्रवाइयों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति अब भी बहुत चिंताजनक है।

उन्होंने तिब्बत से भागने वाले निहत्थे तिब्बतियों पर चीनी सैनिकों की गोलीबारी का जिक्र किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं निरंतर हो रही हैं।

दलाई लामा ने जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए से कहा ''भागने की कोशिश कर रहे अनेक लोगों को गोली मारी गई। चीनी लोग तिब्बती संस्कृति की अनदेखी कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमने देखा है कि भारत में जन्मे तिब्बती लोगों में उन लोगों की तुलना में कई तिब्बती गुण अधिक हैं जो कि तिब्बत में ही जन्मे। पुरानी पीढ़ी बौद्धधर्म के बारे में ज्ञान से भरी हुई थी जो अब लगभग समाप्त ही हो गया है।''

पश्चिमी देशों में अपनी लोकप्रियता के कारण चीन पर दबाव के बारे में दलाई लामा ने कहा, ''मेरा मुख्य उद्देश्य तिब्बती मुद्दा नहीं है। मेरी चिंता मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। लोग मुझसे तिब्बत के बारे में पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे जवाब देना होता है।'' उन्होंने कहा कि चीनी भी तिब्बती बौद्धमत में अधिक रुचि दिखा रहे हैं जिससे तिब्बत के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो रहा है।

संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ तिब्बती विद्यार्थियों की भूख हड़ताल के वह समर्थक नहीं हैं। ''लेकिन मैं उनकी बेचैनी को समझ सकता हूं क्योंकि तिब्बत में सुधार के कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन बौद्ध विचार से मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि आत्महत्या भी एक तरह की हिंसा है।''

यह पूछे जाने पर क्या वह अंतिम दलाई लामा होंगे, उन्होंने कहा, ''जैसा कि मैं प्रायः कहता हूं कि दलाई लामा का यह संस्थान तब तक बना रहेगा जब तक यह तिब्बती लोगों के लिये उपयोगी होगा। वे नहीं चाहेंगे तो दलाई लामा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे बाद भी तिब्बती लोगों को इस संस्थान की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा ''अगर तिब्बत में स्थिति अगले 20–30 साल तक निरंतर सुधरती है तो तिब्बती यह फैसला कर सकते हैं कि दलाई लामा की आवश्यकता नहीं बची है। मैं 14वें दलाई लामा के रूप में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं पर शायद सबसे बुरे भी नहीं हूं।

यह पूछे जाने पर क्या वह अंतिम दलाई लामा होंगे, उन्होंने कहा, ''जैसा कि मैं प्रायः कहता हूं कि दलाई लामा का यह संस्थान तब तक बना रहेगा जब तक यह तिब्बती लोगों के लिये उपयोगी होगा।'' अगर तिब्बती लोगों का बहुमत यह मानेगा कि अब दलाई लामा की जरूरत नहीं है तो कोई दलाई लामा नहीं रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे बाद भी तिब्बती लोगों को इस संस्थान की जरूरत होगी।